समक्ष

श्री एस. एस. संधावालिया माननीय न्यायमूर्ति और श्री आई. एस. तिवाना माननीय न्यायमूर्ति

एन, सी महेंद्र, - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड और

अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 4088 का 1978.

9 मई, 1983।

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 226 और 227 - सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V) - आदेश 41 - रिट अधिकार क्षेत्र - क्या अपीलीय प्रकृति का प्रयोग - रिट याचिका - की स्वीकृति - किसी विशेष प्रश्न तक सीमित हो सकती है।

ये निर्धारित किया गया कि रिट क्षेत्राधिकार प्रकृति में *सख्त अपीलीय* नहीं है। यह देखने के लिए कोई बड़ी समझ की आवश्यकता नहीं है कि कई प्रसिद्ध रिट संक्षेप में दूर-दूर तक अपीलीय नहीं हैं। उदाहरण के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रसिद्ध रिट को किसी विशिष्ट आदेश के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा सकता है और केवल अनधिकृत हिरासत

के तथ्य के खिलाफ राहत का दावा कर सकता है। इसी तरह, निषेध और यथास्थिति वारंट की रिट को समान रूप से किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा सकता है। स्थिति समान है यदि मैंडमस रिट के मामले में भी समान नहीं है । यहां तक कि *सर्टिओररी* रिट के मामले में, यह लचीले ढंग से नहीं कहा जा सकता है कि यह अपील की प्रकृति को दर्शाता है। वास्तव में, इस बिंदु पर कानून इस सिद्धांत की पुनरावृत्ति के साथ पवित्र है कि रिट क्षेत्राधिकार एक अपीलीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(पैरा 6)

ये निर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41, जैसा कि इसके शीर्षक से संकेत मिलता है, मूल डिक्री से अपील से संबंधित है। भाषा के साथ हिंसा किए बिना, कोई भी आसानी से एक रिट याचिका को मूल डिक्री से अपील के रूप में कल्पना नहीं कर सकता है। फलस्वरूप। इस आदेश के प्रावधान *प्रथम दृष्टया* आकर्षित नहीं किए जा सकते हैं। यह प्रवेश को लिस के एक हिस्से तक सीमित करने के लिए खुला है और जरूरी नहीं कि यह पूरे के लिए हो। दरअसल, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य चीजों के अलावा, यह रिकॉर्ड की अदालत की अंतर्निहित शक्ति से भी बह सकता है। इसके अलावा, भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 226 में उल्लिखित उच्च विशेषाधिकार रिट को पूर्ण प्रक्रियात्मक सीमाओं के प्रोक्रस्टियन बेड तक सीमित नहीं किया जाना

चाहिए। यह अच्छी तरह से तय है कि उच्च विशेषाधिकार रिट पर लागू अंग्रेजी कानून के सामान्य सिद्धांतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, 139 और 226 के आधार पर शामिल किया गया है और जारी रखा गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन रिट ों को जारी करने का अधिकार प्राप्त रिकॉर्ड न्यायालय के पास राहत को सीमित करने या संशोधित करने की अंतर्निहित शक्ति होगी। इस दृष्टिकोण का सबसे मजबूत, यदि निर्णायक नहीं, तो स्थापित कानून से प्राप्त होता है कि रिट क्षेत्राधिकार में राहत देने की शक्ति विवेकाधीन है और इसे पूर्ण अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। रिट अदालत, निश्चित रूप से अपने विवेक में (भले ही यह आवश्यक रूप से न्यायिक होना चाहिए) विभिन्न कारणों से रिट जारी करने से इनकार कर सकती है। वास्तव में, यह एक रिट के माध्यम से उपाय और मुकदमे के माध्यम से उपाय के बीच तेज अंतर का बिंदु है, जबकि बाद में राहत का दावा किया जा सकता है / यह केवल पूर्व में विवेकाधीन है। अब यदि किसी रिट याचिका में कई कारणों से राहत देने से इनकार किया जा सकता है, तो इसका मतलब यह होगा कि इसे आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जा सकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि पूरे में हिस्सा शामिल है, और अगर राहत को पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है, तो इसे स्पष्ट रूप से आंशिक रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। इसे इसके विपरीत रखने के लिए, राहत की प्रार्थना केवल पूरे दावे के एक हिस्से तक सीमित हो सकती है। यह बड़ा परिप्रेक्ष्य पहले के अंग्रेजी

कानून के साथ-साथ अब इस अधिकार क्षेत्र के भीतर भी आम है।

(पैरा 9, 10 और 11)

माननीय न्यायमूर्ति आई एस तिवाना की एकल पीठ द्वारा 16 फरवरी, 1982 *को इस मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला भेजा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति आई एस तिवाना की वृहद पीठ ने अंततः मामले का फैसला किया।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका *में प्रार्थना की गई है कि: –*

(1) आदेशों को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी *की* प्रकृति में एक रिट, *अनुलग्नक पी-9 और अनुलग्नक* पी -10 जारी किया जाए।

(2) *मंडामस* की प्रकृति में एक रिट *जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है।* 1 *और 2 16 तारीख* से पहले की तारीख से अधीक्षण अभियंता *के पद पर* पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता पर विचार करना। *मई,* 1974 *को जब याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था, तब आदेश जारी किया जाए।*

(3) मंडामस की प्रकृति में एक रिट *है कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता नियमों के अनुसार तय की जाए और उसे प्रतिवादी संख्या 10 से वरिष्ठ घोषित किया जाए।* 3 *से* 16 *जो कार्यकारी अभियंता के पद पर याचिकाकर्ता से जूनियर हैं, उन्हें जारी किया जाए।*

(4) मामले का रिकॉर्ड भेजा जाए।

(5) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत दी जाए।

कुलदीप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता *याचिकाकर्ता के लिए।* गोपी चंद और उनके साथ एस. एस. शेरगिल।

प्रतिवादी के वकील *ए. एस. नेहरा।*

निर्णय

श्री एस. एस. संधावालिया माननीय न्यायमूर्ति

1. क्या रिट कोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका में *किसी* याचिका के दायरे को केवल एक या अधिक विशिष्ट आधारों तक सीमित करने का अधिकार है, इसे स्वीकार करने के प्रारंभिक चरण में, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके कारण डिवीजन बेंच को यह संदर्भ देना आवश्यक हो गया।

2. एन.सी. महेंद्र याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के तहत एक कार्यकारी अभियंता के रूप में काम कर रहे थे, जब **4** नवंबर,

1974 को उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के मद्देनजर उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 13 जनवरी, 1975 को उन्हें विधिवत आरोप-पत्र दिया गया और उसके बाद जांच पूरी होने के बाद, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया कि क्यों न उनकी तीन वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी जाएं। 11 जुलाई, 1977 को उन्होंने इसका उत्तर प्रस्तुत किया। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें कोई सजा नहीं दी गई और बाद में उन्हें 13 सितंबर, 1977 के आदेश, अनुलग्नक पी. 2 के माध्यम से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। उसे वहां से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना था।

3. बाद में 2 दिसंबर, 1977 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-अधिकारियों को एक विस्तृत अभ्यावेदन अनुलग्नक पी.8 प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें पिछली तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नत किया जाना चाहिए जब उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था। परिणामी राहत के परिणामस्वरूप उनके सहयोगियों की तुलना में उनकी वरिष्ठता में तदनुसार परिवर्तन किया जाए और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से फिर से वेतन और भत्तों के बारे में लाभ दिए जाएं। याचिकाकर्ता के अनुसार, जिस तारीख से उन्होंने इन सभी लाभों का दावा किया, वह

16 मई, 1974 थी। इस प्रतिवेदन के उत्तर में उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 *1,-अनुपत्र पी-9 के माध्यम* से सूचित किया गया था। दिनांक 7 जुलाई, 1978 के पृष्ठ 9 में कहा गया है कि पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन और भत्तों के लिए उनका दावा गलत था क्योंकि उन्होंने पदोन्नत रैंक पर उस अवधि के दौरान काम नहीं किया था। हालांकि, पूर्वव्यापी प्रभाव और वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के लिए उनके अनुरोध को विचाराधीन रखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के मामले पर हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 9 सितंबर, 1977 को अपनी बैठक में विधिवत विचार किया गया था, जो निम्नानुसार हल किया गया था: –

उन्होंने कहा, 'पिछले तीन साल से पदोन्नति से उनकी अनदेखी की जा रही है, जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त दंड है. यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, श्री महेंद्र के खिलाफ मामले को बंद किया जा सकता है और उनके खिलाफ अब तक की गई कार्यवाही अगले अवसर पर उनकी पदोन्नति के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए।

उपर्युक्त बोर्ड के निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 31 अगस्त, 1978 के अनुलग्नक पी-10 के माध्यम से सूचित किया गया था कि

पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी लाभ की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता और 2 दिसंबर, 1977 के उनके अभ्यावेदन को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था /

4.याचिका दायर करने वाले 1 ने विभिन्न आधारों पर उपरोक्त आदेश को चुनौती दी और प्रस्ताव पीठ ने प्रस्ताव का नोटिस जारी किया। इसके जवाब में प्रतिवादियों 1 और 2 की ओर से 9 नवंबर, 1978 को एक रिटर्न दाखिल किया गया और मामले को बहस के लिए स्थगित कर दिया गया। दलीलों के आधार पर और वकील को सुनने के बाद प्रस्ताव पीठ ने निम्नलिखित आदेश दर्ज किया -

> उन्होंने कहा, "केवल वरिष्ठता और निलंबन की अवधि के वेतन के संबंध में भर्ती किया गया है। बहुत जल्दी।

जब यह मामला पहली बार मेरे विद्वान भाई आई. एस. तिवाना, जे,., के समक्ष आया, तो याचिकाकर्ता की ओर से छह विशिष्ट विवाद उठाए जाने की मांग की गई थी। हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति की गई थी कि रिट याचिकाकर्ता को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और मामले को मोशन बेंच के आदेश के कारण निलंबन की अवधि के लिए केवल वरिष्ठता और वेतन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। रिट याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रारंभिक आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 11

और 12 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम का दायरा बढ़ा दिया गया है। पूर्व-निर्धारित आदेश के बावजूद चुनौती को प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता था। इस मामले में कुछ विसंगतियों को देखते हुए मामले को खंडपीठ द्वारा निर्णय के लिए भेज दिया गया था।

5.एकल पीठ के समक्ष, इसलिए हमारे समक्ष, याचिकाकर्ता की ओर से श्री कुलदीप सिंह का प्राथमिक तर्क यह था कि रिट क्षेत्राधिकार संक्षेप में, प्रकृति में अपीलीय है या इसके समान विकल्प में है। इस मूल आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 11 और 12 के प्रावधानों को लागू किया गया था (रिट क्षेत्राधिकार (पंजाब हरियाणा पर) नियम, 1976 के नियम 32 के आधार पर, यह तर्क देने के लिए कि रिट याचिका को स्वीकार किए जाने के बाद, पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए और इसे प्रस्ताव पीठ द्वारा सीमित या सीमित नहीं किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर, **वट्टीपल्ले ईश्वरैया बनाम वट्टीपल्ले ईश्वरैया पर भरोसा किया गया था।वट्टीपल्ले रामेश्वरय्या और सात अन्य**[1], जिसका अनुसरण **काशी विश्वनाथन चेट्टियार और अन्य बनाम सी. एम. चिन्नैया चेट्टियार**[2], में किया गया है।

6.उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यहां मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या रिट आदेश प्रकृति में *सख्त अपीलीय* है। इसके बाद के कारणों के लिए, इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरा मानना है कि यह देखने के लिए कोई बड़ी समझ की आवश्यकता नहीं है कि

[1] आईएलआर (1940) मद्रास 785।

[2] 1977 (2) मैड. एल.जे. 524.

कई प्रसिद्ध रिट गर्म हैं, यहां तक कि संक्षेप में दूर से भी अपीलीय हैं। उदाहरण के लिए, *बंदी प्रत्यक्षीकरण* की प्रसिद्ध रिट को किसी विशिष्ट आदेश के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा सकता है और केवल अनधिकृत हिरासत के तथ्य के खिलाफ राहत का दावा किया जा सकता है। इसी तरह, निषेध और यथास्थिति वारंट की रिट को समान रूप से किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश के खिलाफ निर्देशित नहीं किया जा सकता है। स्थिति समान है यदि मैंडमस रिट के मामले में भी समान नहीं है । यहां तक कि *सर्टिओररी* रिट के मामले में, यह लचीले ढंग से नहीं कहा जा सकता है कि यह अपील की प्रकृति को दर्शाता है। वास्तव में, इस बिंदु पर कानून इस सिद्धांत की पुनरावृत्ति के साथ पवित्र है कि रिट क्षेत्राधिकार एक अपीलीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

7.अब सिद्धांत के अलावा, यह मामला बाध्यकारी मिसाल द्वारा समान रूप से कवर किया गया प्रतीत होता है। उसी को गुणा करना अनावश्यक है। ऐतिहासिक मामले में, **हरि विष्णु कामथ वी। अहमद इशाक और अन्य**[3], यह स्पष्ट रूप से निम्नानुसार देखा गया है: –

> "न्यायालय ने 'सर्टिओरारी' की रिट जारी की पर्यवेक्षी के प्रयोग में कार्य करता है न कि अपीलीय अधिकार *क्षेत्र में*। इसका परिणाम यह है कि न्यायालय अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण

[3] एआईआर 1955 एस.सी. 233।

> द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर है कि एक न्यायालय जिसके पास किसी विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र है, उसके पास गलत और साथ ही सही का फैसला करने का अधिकार है, और जब विधायिका उस निर्णय के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनती है, तो यह अपने उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा, अगर एक वरिष्ठ न्यायालय साक्ष्य पर मामले की फिर से सुनवाई करता है, और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रमाणात्मक में प्रतिस्थापित *करें* ये प्रस्ताव अच्छी तरह से तय हैं और विवाद में नहीं हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस पूर्ण दलील को खारिज किया जाना चाहिए कि रिट ज्यूरी डिक्शन एक अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, जो अनिवार्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 को आकर्षित करता है।

8.इसके अलावा, टी विकल्प में 11 मेलोवेडिक्ट स्टैंड यह है कि यदि रिट क्षेत्राधिकार अपीलीय मंच के समान है, तो भी इसमें कोई दम नहीं है। **एम. आर. चन्नारायपा बनाम तहसीलदार और निर्वाचन अधिकारी, मलूर और एक अन्य**[4] कुछ इसी तरह का प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालय रिट

[4] एआईआर 1980 कर्नाटक 72

कार्यवाही नियम, 1977 के नियम 39 (जो रिट क्षेत्राधिकार (पंजाब और हरियाणा) नियम, 1976 के नियम 32 के अनुरूप प्रतीत होता है) के संदर्भ में उठाया गया था, इसे निम्नानुसार माना गया था: -

".....नियमों के अनुच्छेद 39 द्वारा, निम्नलिखित के प्रावधान

> नियमों द्वारा विशेष रूप से निपटाए नहीं जाने वाले मामलों में और जिस हद तक वे आवश्यक हैं, सिविल पी.सी. को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही के लिए लागू किया जाता है। प्रक्रिया के मामलों में, इस संदर्भ में आवश्यक संशोधनों के साथ संहिता में किए गए प्रावधानों पर भरोसा करने की अनुमति है। इसलिए, मेरी राय है कि सीपीसी का 0.27 इस न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही पर लागू होता है। *सी के* 0.27 *में। जहां भी 'मुकदमा' शब्द आता है, हमें 'रिट याचिका' शब्द पढ़ना पड़ता है।*

उपरोक्त टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था और पूर्ण पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी। **तेजा सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य**[5]

[5] 1981(1) एस.एल.आर. 274.

9.इसके बाद यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि 0.41, यह एक बहुत ही शीर्षक इंगित करता है, मूल डिक्री से अपील से संबंधित है। भाषा के साथ हिंसा किए बिना, कोई भी आसानी से एक रिट याचिका को मूल डिक्री से अपील के रूप में कल्पना नहीं कर सकता है। नतीजतन, इस आदेश के प्रावधान *प्रथम दृष्टया तथ्यों* को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि यह मानते हुए भी (हालांकि, पूरी तरह से तर्क के लिए), मैं यह कहना चाहता हूं कि रिट याचिकाकर्ता के मामले को सर्वोच्च स्तर पर रखने के बावजूद, यह मामला फिर से पूरी तरह से उनके पक्ष में नहीं लगता है, यहां तक कि इस अपीलीय मामले की सख्ती में भी। निस्संदेह, *वैतीपल्ले ईश्वरैया के मामले* (सुप्रा) में टिप्पणियां और उसमें दृष्टिकोण रिट याचिकाकर्ता की ओर से लिए गए रुख के समर्थन में जाते हैं। तथापि, एक समान रूप से प्रतिष्ठित पीठ की अध्यक्षता सर जॉन ब्यूमोंट, सीजे ने **करिष्णाजी श्रीनिवास जलवाड़ी और अन्य बनाम मधुसा अप्पनसा लदाबा**[6] मामले में निम्नानुसार देखा है: –

" ..... हम यहां तक जाने के लिए तैयार नहीं हैं।श्री मुरुदेश्वर और यह कहना कि अपील को पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए या पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है। यदि कोई अपील विच्छेदयोग्य है, तो नियम 11 के तहत अपील की सुनवाई

[6] (1933) 58 आई.एल.आर. बम. 406

करने वाले न्यायाधीश के लिए इसे आंशिक रूप से खारिज करने और इसे आंशिक रूप से स्वीकार करने का विकल्प खुला है; जैसे कि अंतिम सुनवाई में न्यायालय अपील को आंशिक रूप से खारिज कर सकता है और इसे आंशिक रूप से अनुमति दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपील दो सर्वेक्षण संख्याओं से संबंधित है, जो अलग-अलग शीर्षकों के तहत आयोजित की जाती हैं, तो हमें अदालत द्वारा अपील को खारिज करने और दूसरे सर्वेक्षण संख्या के रूप में नोटिस जारी करने का निर्देश देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

रेखा ठाकुर बनाम रामनंदन राय[7] मामले में डिवीजन बेंच की ओर से फजल अली ने भी अपनी बात रखी / को निम्नानुसार रखा गया:-

> "* * *. साथ ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आदेश 41, नियम 11 के तहत अपील की सुनवाई के समय, अपीलीय न्यायालय को सूचित किया जाता है कि अपील केवल कुछ निर्दिष्ट आधारों तक ही सीमित रहेगी और अन्य आधारों को छोड़ दिया जाएगा या यदि अपीलकर्ता की ओर से यह स्वीकार कर लिया जाता है कि निर्दिष्ट आधारों के अलावा अन्य आधार अपील में आग्रह करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, आदेश 41, नियम 11 के तहत जिस अदालत के समक्ष अपील रखी गई है,

[7] (1936) 15 आई.एल.आर.पटना 96.

उसे इस तथ्य को नोट करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के सख्त मापदंडों के भीतर भी, मतभेद प्रतीत होता है और अधिकार की कमी नहीं है कि अपील को स्वीकार करना एक या अधिक स्पष्ट मुद्दों तक ही सीमित हो सकता है। इस प्रकार संहिता के तहत पसंद किए गए मूल डिक्री से अपील के संदर्भ में भी मिसाल इस बिंदु पर विभाजित है और मैं अपने पहले के निष्कर्ष के मद्देनजर इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मजबूर महसूस नहीं करता कि रिट क्षेत्राधिकार वास्तव में अपीलीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

10.इस संदर्भ में, यह ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार के निर्दिष्ट मंच में भी अंतिम न्यायालय ने स्वीकार की गई अपीलों को केवल एक सीमित बिंदु तक सीमित कर दिया है। यह विवाद में नहीं है, हालांकि रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अस्पष्ट रूप से यह तर्क देने का प्रयास किया था कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा आवश्यक हो सकता है, हालांकि केवल सीमित आधार पर अपील को स्वीकार करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान हमारे विचार में नहीं लाया जा सकता है। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, मैं इस तथ्य से समर्थन लेने के लिए तैयार हूं कि उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील ों के अंतिम चरण में भी, प्रवेश को इसके एक हिस्से तक सीमित करने

के लिए खुला है और जरूरी नहीं कि यह पूरे तक हो। दरअसल, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य चीजों के अलावा, यह रिकॉर्ड की अदालत की अंतर्निहित शक्ति से भी बह सकता है।

11.उपर्युक्त बातों को *ध्यान में रखते* हुए मैं विशेष रूप से इस व्यापक सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उल्लिखित उच्च विशेषाधिकार रिट को पूर्ण प्रक्रियात्मक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय है कि उच्च विशेषाधिकार रिट पर लागू अंग्रेजी कानून के सामान्य सिद्धांतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32, 139 और 226 के आधार पर शामिल किया गया है और जारी रखा गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन रिट ों को जारी करने का अधिकार प्राप्त रिकॉर्ड न्यायालय के पास राहत को सीमित करने या संशोधित करने की अंतर्निहित शक्ति होगी। इस दृष्टिकोण का सबसे मजबूत, यदि निर्णायक नहीं, समर्थन स्थापित कानून से प्राप्त होता है कि कानून में राहत देने की शक्ति है। रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है और इसे पूर्ण अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। रिट अदालत, निश्चित रूप से अपने विवेक में (भले ही यह आवश्यक रूप से न्यायिक होना चाहिए) विभिन्न कारणों से रिट जारी करने से इनकार कर सकती है। वास्तव में यह तीव्र भेद का विषय है।

रिट के माध्यम से उपाय और मुकदमे के माध्यम से के बीच, जबकि बाद में राहत का दावा न्याय के लिए किया जा सकता *है।* यह केवल पूर्व में विवेकाधीन है। अब यदि किसी रिट याचिका में कई कारणों से राहत देने से इनकार किया जा सकता है, तो इसका मतलब यह होगा कि इसे आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जा सकता है। यह स्वयंसिद्ध है कि पूरे में हिस्सा शामिल है, और अगर राहत को पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है, तो इसे स्पष्ट रूप से आंशिक रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। इसे इसके विपरीत रखने के लिए, राहत की प्रार्थना केवल पूरे दावे के एक हिस्से तक सीमित हो सकती है। यह बड़ा परिप्रेक्ष्य पहले के अंग्रेजी कानून के साथ-साथ अब इस अधिकार क्षेत्र के भीतर भी आम है। 'द क्वीन वी' में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की निम्नलिखित टिप्पणियों को याद करते हुए किसी को और पीछे जाने की जरूरत नहीं *है।*

रानी बनाम सभी संतों विगन और अन्य (7-ए) (1876) ऐप। केस 611.

के निम्नानुसार हैं: –

> उन्होंने कहा, 'अब मुझे लगता है कि इस विषय पर कुछ भ्रम की स्थिति है, जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। एक रिट *मैंडामस* यह एक विशेषाधिकार रिट है और अधिकार की रिट

नहीं है, और यह इस अर्थ में न्यायालय के विवेक पर है कि इसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं। न्यायालय न केवल गुण-दोष के आधार पर, बल्कि कुछ देरी पर, या अन्य मामले पर, इसके लिए आवेदन करने वाले पक्ष के व्यक्तिगत आधार पर रिट देने से इनकार कर सकता है; इसमें न्यायालय एक विवेकाधिकार का प्रयोग करता है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में जहां रिघ, टी के संबंध में एक नियम है *मैंडामस* यदि कारण दिखाया गया है, तो कारण संदिग्ध प्रतीत होने पर, अदालत अक्सर अनुमति देती है *मैंडामस* ताकि वापसी पर अधिकार का प्रयास किया जा सके; यह भी विवेक का विषय है-

---------- ".

उपर्युक्त मूल प्रस्ताव के समर्थन में बड़े पैमाने पर उद्धृत करना व्यर्थ होगा और संदर्भ शिक्षाप्रद रूप से **रानी बनाम गारलैंड**[8] को दिया जा सकता है और ***रानी* बनाम *ग्रेंटवुड सुप्ट विवाह रजिस्ट्रार पूर्व पी एरियस***[9]।

(12) इस देश के उच्च न्यायालयों में एक समान अवैध स्थिति ने बार-बार यह माना है कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है। संपूर्ण होने के बिना, यह

[8] (1870) 5 क्यू.बी. 269 (272).
[9] (1968) 2 क्यू. बी. 956 (970)।

स्थापित कानून है कि न्यायालय आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में रिट जारी नहीं करेगा, जिसके पास (i) पर्याप्त वैकल्पिक उपाय है, (ii) जो देरी का दोषी है जो अस्पष्ट है, (iii) जो उसे राहत देने वाले आचरण का दोषी है, (iv) जहां न्याय के हित में यह आवश्यक नहीं है कि राहत दी जानी चाहिए, (v) जहां याचिकाकर्ता तथ्य का विवादित प्रश्न उठाता है, (vi) जहां रिट प्रदान करना व्यर्थ होगा, और, (vii) जहां लागू कानून लागू नहीं हुआ है। उपरोक्त से यह पता चलता है कि रिट को देना या अस्वीकार करना न्यायालय के न्यायिक विवेक के भीतर है और वास्तव में यही वह रेखा है जो सिविल मुकदमे के माध्यम से असाधारण उपाय को साधारण से विभाजित करती है।

13.अब एक बार जब यह तय हो जाता है, जैसा कि अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कि राहत का दावा करने का अधिकार न्यायालय के विवेक के अधीन है, यदि राहत को पूरी तरह से अस्वीकार करने के बजाय, यह न्यायालय द्वारा सीमित या सीमित है, तो संभवतः इसके साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए, प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर हां में दिया जाना चाहिए और यह माना जाता है कि प्रस्ताव पीठ को किसी रिट याचिका के प्रवेश को केवल एक या अधिक विशिष्ट आधारों तक सीमित करने का अधिकार है।

14.एक बार जब इसे उपरोक्त माना जाता है, तो याचिकाकर्ता के विद्वान

वकील ने यह कहने के लिए पर्याप्त निष्पक्ष था कि जिन सीमित मुद्दों पर प्रवेश सीमित था, उनके पास आग्रह करने के लिए बहुत कम या वास्तव में कुछ भी नहीं था। माना जाता है कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सर्वोच्च निकाय ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया था और अच्छे कारणों से पूर्वव्यापी प्रभाव से लाभ के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया था। जाहिर है, याचिकाकर्ता को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एक मानित तिथि से पदोन्नति का दावा करने और उससे वेतन और वरिष्ठता के परिणामी लाभों का दावा करने का कोई लचीला अधिकार नहीं है। वह अधिक से अधिक उस मामले पर विचार करने का दावा कर सकते हैं जो माना जा चुका है। स्पष्ट रूप से, कोई भी *परमादेश* यह जारी नहीं कर सकता है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति की एक काल्पनिक तारीख दी जानी चाहिए, जबकि वास्तव में, इस तरह की पदोन्नति बहुत बाद में 13 सितंबर, 1977 को हुई थी। परिणामस्वरूप लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन
सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
पानीपत, हरियाणा।